water supply arrangements. There is also a regular distribution system through pipe-lines in all the collieries and stand-posts have been provided in Dhowrahs. However, an integrated water supply scheme for this area is being formulated.

कोयला खान कल्याण भविष्य निधि आयुक्त धनबाद द्वारा कोयला खान श्रमिक कल्याण भविष्य निधि के अधीन विनियोजित राशि में राज्य का अंश

3953. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिक कल्याण भविष्य निधि के अन्तर्गत कुल विनियोजित निधि में से विभिन्न राज्यों का भाग अकेले कोयला खान श्रमिक कल्याण भविष्य निधि, धनबाद के आयुक्त द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और उनके भागों के निर्धारण में आयुक्त, संयुक्त राष्ट्रीय बचत, नागपुर का कोई अधिकार नहीं होता ;

(ख) क्या अंशों के निर्धारण के लिए कुछ विशिष्ट नियम हैं और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार विभिन्न राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धान्त बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या प्रति वर्ष बिहार का भाग लगातार घटता जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अलग-अलग दो निधियां चल रही हैं जिन्हें "कोयला खान भविष्य निधि" और "कोयला खान श्रम कल्याण निधि" कहा जाता है। परन्तु "कोयला खान श्रम कल्याण भविष्य निधि" नाम की कोई निधि नहीं है और न ही कोई आयुक्त ऐसा है जिसे "कोयला खान श्रम कल्याण भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद" कहा जाता है। अतः बाकी सवालों का प्रश्न ही नहीं उठता।

Rules for Advertisement by Foreign Missions

3954. SHR CHITTA BASU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Press Council remitted back to the External Affairs Ministry its proposal for framing rules governing acceptance by the Indian Press of advertisements from foreign missions denouncing third countries with which India has friendly relations; and

(b) if so, further steps taken by Government in that direction?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir.

(b) The matter was taken up suitably with all Foreign Diplomatic Missions in the Country by the Ministry of External Affairs.

12 hrs.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): I would draw your attention to something that appeared in yesterday's proceedings. I had said about my notice under Rule 222 about postal censorship and you had said:

> "I have written to our High Commissioner to get a Report from the Parliament in Australia. I am trying to do something. I think the main thing will be to change the Act."

Two things you have done. One is that you asked for documents from Australia; and two, you think that unless the Act is changed, question of privilege would not arise. I would like to submit to you my privilege motion was not that. First of all, as far as your writing to Australia is concerned, I think your mail service is even more inefficient than mine. I